[Shri Pranab Mukherjee]

hitherto. They will be instructed not to make any policy pronoucements which are not already incorporated in the budget. It shall, of course, be my duty and privilege to provide all information and explanations required by Hon'ble Members, on the floor of Parliament.

SHRI HARIKESH BAHADUR: (Gorakhpur) : Is there any Gujral ?

(Interruptions)

DR. SUBRAMANIAM SWAMY (Bombay North East) : I hope, Sir, this will be a special case for this Minister.

(Interruptions)

MR. DEPUTY SPEAKER : It was an observation.

12.48 hrs.

BUSINESS OF THE HOUSE

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI P. VENKATASUBBAIAH): With your permission, Sir, I rise to announce that Government Business in this House during the week commencing 1st March, 1982 will consist of :—

1. Consideration of any item of Government Business carried over from today's Order Paper.

2. Consideration of amendments made by the Rajya Sabha in the African Deveopment Fund Bill, 1981.

3. General discussion on the Railway Budget for 1982-83.

4. Further consideration and passing of the Sugar Cess Bill, 1981 and the Sugar Development Fund Bill, 1981.

5. Consideration and passing of:—

   (a) The Central Silk Board (Amendment) Bill, 1981.

   (b) The Wild Life (Protection) Amendment Bill, 1981.

6. General discussion on the General Budget for 1982-83 from Friday the 5th March, 1982.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: (Bombay North East): Sir, I have a point of order. In connection with this item.. ..

MR. DEPUTY-SPEAKER : There is a vaccum in the House. You must take my permission to raise the point of order.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: Yes, I am asking your permission under Rule 376. I have requested permission to make a submission. I have been denied it on the ground that my letter did not accompany the full text. In that letter I wrote that I am prepared to submit it. Becuase my plane came late, I had to rush and I had to do this and there was no other way I could do it earlier. So, I would like you to give me special permission to read out what I have to say. This is not a matter of national security that I should be denied that.

MR. DEPUTY SPEAKER : Of course, on a point of clarification you have asked. As decided at the sitting of the Business Advisory Committee held on 16th December 1981, intimations from Members which are not accompanied by the full text would not be considered by the Speaker for grant of permission to make submission.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: But I have explained to you the circumstances in which it has happened. I know the Members who have in the past....

MR. DEPUTY-SPEAKER : You raise this issue again in the Business Advisory Committee.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: But you have power just now. Why don't you do it ?

MR. DEPUTY-SPEAKER : I cannot. I cannot act against the decision of the Business Advisory Committee. Now, Mr. K.M. Madhukar.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY : But, Sir, is it something explosive that you want to prevent me today ?

MR. DEPUTY-SPEAKER : That is all right. Mr. K.M. Madhukar.

श्री कमला मिश्र मधुकर (मोतीहारी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज की कार्य सूची के मद संख्या 4 के सम्बन्ध में निम्नलिखित संशोधन पेश करना चाहता हूं ।

(1) बिहार और उत्तर प्रदेश के गन्ना उत्पादक किसानों को गन्ने की लागत खर्च दर के अनुसार भी गन्ने की कीमत नहीं दी जा रही है । चीनी मिल-मालिकों एवं सरकार की चीनी मिल मालिकों के हित की रक्षा सम्बन्धी नीति की मिली भगत का ही यह परिणाम है । बिहार में इसके खिलाफ हड़तालें भी हुई हैं तथा दो किसानों की हत्या भी रीगा-चीनी मिल में कर दी गई है ।

किसानों के पिछले बकाया रकम का भुगतान आज तक नहीं दिया गया है और वर्तमान भुगतान में भी काफी गड़बड़ियां हैं । किसानों के गन्ने की पूरी पेराई की भी संभावना क्षीण होती जा रही है । गन्ना किसान काफी परेशानियों एवं अनिश्चितता की हालत में हैं ।

अस्तु मेरी मांग है कि गन्ना उत्पादक किसानों की समस्याओं पर अगले सप्ताह लोक सभा में अवश्य चर्चा की जाए ।

(2) पानी के जमाव से पूर्व एवं पश्चिम चम्पारण जिला में किसानों की भारी क्षति है । गण्डक नहर परियोजना के अन्तर्गत जल निस्सारण योजना के कार्यक्रम अति धीमी गति से चल रहा है । ऐसी समस्या हर नदी घाटी योजनाओं की हैं ।

अस्तु नदी घाटी योजनाओं के कार्यों की प्रगति एवं तज्जनिक किसान समस्याओं पर अगले सप्ताह की कार्यसूची में रखी जाए ।

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं संसदीय कार्य मंत्री जी द्वारा आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषयों का भी समावेश किए जाने की प्रार्थना करता हूं :

1. वन संरक्षण अधिनियम 1980 जिस का उद्देश्य वनों का संरक्षण तथा सम्वर्धन पर्यावरण सम्बन्धी संतुलन को बनाए रखना है, के उपबन्ध (2) द्वारा विकास कार्यों में अवरोध पैदा हो रहा है । इस उपबन्ध में तत्काल संशोधन अपेक्षित है, ताकि राज्य सरकारों द्वारा संचालित विकास कार्यों जैसे सड़क, भवन निर्माण, पेयजल योजनाओं तथा विद्युत प्रसार आदि कार्यों में अनावश्यक विलम्ब न होवे । इस समय बन विभाग की भूमि में वनीकरण के अतिरिक्त किए जाने वाले किसी भी कार्य हेतु केन्द्रीय सरकार को अनुमति लेनी पड़ती है । इस कार्य का प्रोसिज्योर इतना विलम्बकारी है कि अनुमति प्राप्त होने तक स्वीकृत योजना का व्यय भार बढ़ जाता है तथा योजना का पुनः आंकलन बनवाकर स्वीकृति प्राप्त करनी होती है । इस प्रक्रिया में कार्य स्वीकृत होने के दो वर्ष उपरान्त भी प्रारम्भ नहीं हो पा रहा है ।

अतः इस उपबन्ध में संशोधन अपेक्षित है ताकि यह अनावश्यक विलम्ब से पैदा जन आक्रोष का समाधान हो सके । अतः

[श्री हरीश रावत]

इस विषय पर तत्काल संसद में चर्चा आवश्यक है।

2. कटक पालिका अधिनियम 1928, वर्तमान जनतांत्रिक भावनाओं मान्यताओं तथा मूल्यों के सर्वथा प्रतिकूल है। इस अधिनियम में व्यापक संशोधन तत्काल अपेक्षित है ताकि कटकपालिकाओं का प्रशासन भी नगरपालिकों के प्रशासन के अनुरूप जन आकांक्षा की पूर्ति करने वाला हो सके।

वर्तमान समय में कटकपालिका क्षेत्रों का नागरिक आबादियों में गहन असंतोष व्याप्त है तो सरकार व रक्षा सेनाओं तथा जनता तीनों के लिए उचित नहीं है।

अतः कटकपालिका अधिनियम में सरकार को तत्काल संशोधन करने के प्रस्ताव के साथ सदन के सम्मुख आना चाहिए। ये विषय अगले सप्ताह की कार्य सूची में शामिल किए जायें।

SHRI G.M. BANATWALLA (Ponnani) : There is need for a discussion on the shocking reports of serious malpractices and corruption with repect to admission to M.B.B.S., and M.D. courses in Delhi. The Hindustan Times in its issue dated February 26, 1982 carries on the front page a detailed report involving university officials at all levels. Amounts upto Rs. 20,000 to Rs. 30,000 have been allegedly paid to manipulate admissions to MBBS and M.D. courses. The students have repeatedly brought this organised racket to the notice of university authorities and have also now addressed a memorandum to the Prime Minister. Prompt action has to be taken and full-fledged equiry must be ordered. A full discussion on the subject should be included in Business for next week.

श्री विजय कुमार यादव: (नालन्दा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं दिनांक 27-2-82 के पुनरीक्षित कार्य सूची के मद सं. 4 में 1 मार्च, 1982 से आरम्भ होने वाले सप्ताह के लिए सरकारी कार्य में निम्नलिखित विषयों को सम्मिलित करने का अनुरोध करता हूं :—

1. देश आर्थिक संकट के गिरफ्त में लगातार फंसता जा रहा है। इस मामले में विदेशों पर इसकी निर्भरता बढ़ती जा रही है। एकाधिकारी घरानें और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का आर्थिक शिकंजा कसता जा रहा है। काला धन ने एक समानान्तर आर्थिक व्यवस्था का रूप धारण कर लिया है।

देश को आर्थिक मामले में आत्मनिर्भर बनाने के निमित्त बड़े पैमाने पर साधन जुटाने के लिए विदेशी और बचे हुए देशी बैंकों, बहुराष्ट्रीय कम्पनियों तथा एकाधिकार घरानों के व्यापारों का अविलम्ब राष्ट्रीयकरण तथा काला धन का जब्त किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः देश की आर्थिक आत्मनिर्भरता के निमित्त उपरोक्त कदमों को उठाने के विषय को अगले सप्ताह की कार्यसूची में विचारार्थ रखा जाय।

2 शिक्षा जगत में लगातार प्रयोग चल रहा है, पर नतीजा प्रतिकूल ही नजर आता है। शैक्षणिक स्तर में ह्रास हो रहा है, पढ़े-लिखे लोगों की, बेरोजगार की फौज खड़ी हो रही है तथा शिक्षित नौजवानों में निराशा फैल रही है। साथ ही आबादी का बहुत बड़ा भाग आज भी शिक्षा से वंचित है।

अतः शिक्षा का जनवादीकरण और रोजगारोन्मुखी बनाया जाना तथा मैट्रिक तक निःशुल्क एवं अनिवार्य किया जाना

देश के सर्वांगीण विकास के लिए अत्यधिक महत्व रखता है ।

अतः उपरोक्त विषयों को विचारार्थ अगले सप्ताह की कार्य-सूची में रखा जाय ।

प्रो० अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं अगले सप्ताह की कार्यसूची में सम्मिलित करने के लिए निम्नलिखित दो सुझाव प्रस्तुत करता हूं :

1. संघ एवं राज्यों के लोक सेवा आयोगों द्वारा संचालित प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रक्रिया से अनावश्यक जटिलता दूर करने का सुझाव ।

2. लोक सेवा आयोगों द्वारा निर्धारित आयु सीमा का बन्धन हटाने का सुझाव ।

1. प्रतियोगी परीक्षाओं का उद्देश्य देश के लिए अच्छे और योग्य अधिकारी का चुनाव करने का है । परीक्षाओं के सुधार के लिए नये-नये नियम बनने के बावजूद भी परीक्षा का स्तर गिरा है और इस की प्रक्रिया में जटिलता आई है । 1980 में कोठारी आयोग के सुझाव के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग की प्रतियोगी परीक्षा के लिए प्राथमिक परीक्षा की पद्धति आरम्भ की गई थी ताकि परीक्षा को गम्भीरता से लेने वाले उपयुक्त प्रतियोगी ही मुख्य परीक्षा तक पहुंच सकें । प्रथम बार यह योग्यता सिद्ध हो जाने के बाद मुख्य प्रतियोगी परीक्षा में असफल होने पर दूसरे वर्ष भी प्रतियोगियों को फिर प्राथमिक परीक्षा की प्रक्रिया से गुजरने की अनिवार्यता समझ में नहीं आती । उन्हें सीधे मुख्य परीक्षा में क्यों नहीं शामिल किया जाता । बार-बार प्राथमिक परीक्षण की प्रक्रिया से लोक सेवा आयोग और परीक्षार्थी दोनों का बोझ बढ़ता है ।

2. प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए संघ लोक सेवा आयोग ने अधिकतम आयु सीमा 28 वर्ष रखी है । विभिन्न राज्यों में यह सीमा 28 से 30 वर्ष के बीच है :—

1. उत्तर प्रदेश में यह सीमा 28 वर्ष है और बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान आदि राज्यों में 30 वर्ष हैं । इस में एक रूपता न रहने से परीक्षार्थियों का असन्तोष उचित प्रतीत होता है ।

2. प्रतियोगी परीक्षा में बैठने की अनुमति केवल तीन बार ही मिलती है, तो अलग से आयु सीमा के बन्धन का औचित्य नहीं प्रतीत होगा ।

3. उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, आदि राज्यों के आदिवासी और पिछड़ी जाति के ग्रामीण युवकों की पढ़ाई देर से आरम्भ होने और उचित अवसर के अभाव में देर से समाप्त होती है । इन पर से आयु का बन्धन हटा लेने से योग्य युवकों को लाभ होगा और आयोग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि तीन बार में ही सफल होने का बन्धन तो है ही ।

Mr. DEPUTY SPEAKER: Shri Harikesh Bahadur. He will be followed by Smt. Geeta Mukherjee.

SHRI HARIKESH BAHADUR (Gorakhpur): Sir, there are problems in almost all the Central Universites. B.H.U. was closed earlier but now it is reopened. There is crisis in the Delhi University and we find some troubles in the Aligarh Muslim University and J.N. University also. Therefore, a discussion should be allowed on this subject during the next week.

Second point. Many Indian prisoners of war have been missing since 1971 Indo-Pak war. Previously, it was said that they were in Pakistan but now it is said that nothing is known about them. It is a matter of grave concern. Therefore, this should be discussed thoroughly in the House during the next week.

13.00 hrs.

SHRIMATI GEETA MUKHERJEE (Panskura): Mr. Deputy-Speaker, Sir I want to raise following two points for inclusion in the next week's business for the House.

(1) The near-collapse of the rationing system is in evidence in the deficit State of West Bengal due to the most inadequate supply of foodrains from the FCI godowns in West Bengal as well as for lessing the foodgrains allocation quota from the Centre. In this deficit State where statutory rationing is entirely the responsibility of the Central, the allocation falls far short of requiremrnt actual arrival is even less than and the supply from FCI godowns is miserable. Due to this the foodgrain prices are rising. This question should be specifically discussed.

(2) West Bengal Government's suggestion for a Central directive to laid down that at least 50 per cent of the aggregate public borrowings undertaken in a year should be earmarked for the States (including the State Electricity Under takings) as well as its suggestion that the Planning Commission should issue a directive to the Union Government that 40 percent of the revenue raised in the current fiscal year through the adjustment of administered prices of petroleum products, fertilisers, coal, aluminium, iron and steel products should be transferred to the State Government should be discussed.

श्री चतुर्भुज (झालावाड़) : उपाध्यक्ष महोदय, अगले सप्ताह लोक सभा की कार्य सूची में निम्न कार्य विषयों को जोड़ा जाये :

1. अफ़ीम उत्पादक कृषकों को इस वर्ष गत वर्षों से भी कम भाव दिया जा रहा है । अफ़ीम तौल का समय नजदीक है । नारकोटिक्स विभाग निरंकुश है । इस विभाग की प्रशासनिक प्रक्रिया 60–70 वर्ष पुरानी है । अत: इस विभाग को वर्द्धमान स्वरूप प्रदान करें । अफ़ीम उत्पादक कृषकों को लाइसेंस प्रणाली एवं भाव बढ़ाने के लिए सदन में बहस होनी चाहिए । अगले सप्ताह में इस को कार्य दिवस में शामिल किया जावे ।
2. देश में गौवध बन्द हो । कृषक वर्ग एवं राष्ट्र की यह आवश्यक मांग है । इस हेतु देश के महात्माओं ने केन्द्र सरकार का ध्यान आकर्षित किया है । अत: इस विषय को अगले सप्ताह में लिया जाये ।

PROF. MADHU DANDAVATE (Rajapur): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I suggest the following two items to be included in the Government business for the next week.

(1) Lok Pal Bill to prevent corruption in high places. The corruption in high places is polluting the public life in our country. The Lok Pal Bill providing for speedy and special inquiry into the corruption in high places was before the Parliament during the tenure of the Janata Government. However, with the premature fall of that Government, the Lok Pal Bill also became infructuous. I suggest that the Lok Pal Bill be revived and taken up for consideration in this House.

(2) One union in one Industry.

'The principle of one union in one Industry' is desirable both from the point of view of workers as well as management. On the one hand, it will avoid destructive trade union rivalry and strengthen the bargaining power of the workers and on the other it will make the task of the management easy in settling the industrial disputes. The issue of representative character of a union in an industry can be settled by workers' secret ballot in the concerned indudstry. I suggest that a Bill in this regard be brought before the House without further delay.

SHRI P. VENKATASUBBAIAH: Sir, the hon. Members have made various valuable suggestions in regard to matters to brought before the House and discussed.

Even in the last meeting of the Business Advisory Committee also, as you go through the proceedings of the Business Advisory Committee, this is what it recommended. I quote:

> "The Committee further recommended that in order to provide time for the completion of urgent financial business, Half-An-Hour Discussions, Discussions under rule 193 or Discussions under No-Date-Yet-Named motions may be taken up at 6 P.M. and not more than one Half-An-Hour Discussion, Discussion under rule 193 or Discussion under No-Date-Yet-Named motion to be put down in a week till the disposal of of the financial business."

These are the constrains imposed. These matters could be discussed only when the financial business is over. All these matters have been taken note of. They have made very good suggestions. Today also, there has been a lenghty Calling Attention on remunerative prices for potatoes and sugarcane in the House. Other matters which the hon. Members have brought to the notice of the House be placed before the Business Advisory Committee for considration and their approval.

13.00 hrs.

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till five minutes past Fourteen of the Clock.

The Lok Sabha re-assembled after lunch at five minutes past Fourteen of the Clock.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

AN HON. MEMBER: These benches are all empty. No interest.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Ask the Professor.

MOTION OF THANKS ON THE PRESIDENT'S ADDRESS—*Contd.*

MR. DEPUTY-SPEAKER: The House will now take up furhter consideration of the following motion moved by Prof. N.G. Ranga and seconded by Shri H.K.L. Bhagat on the 23rd February, 1982, namely:—

"That an Address be presented to the President in the following terms:

'That the Members of Lok Sabha assembled in this Session are deeply grateful to the President for the Address which he has been pleased to deliver to both Houses of Parliament assembled together on the 18th February, 1982".

As also further consideration of Amendments moved thereto.

I think Mr. Sunder Singh has concluded yesterday. Therefore, you can sit down.

श्री सुन्दर सिंह (फिल्लौर) : बस थोड़ा सा और बोलूंगा ।

MR. DEPUTY-SPEAKER: All right. I will give you two more minutes. Please conclude. He wants to conclude within two minutes. All the rest he has exhausted yesterday.

श्री सुन्दर सिंह : मैं कल राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर बोल रहा था । इसमें कोई शक नहीं है कि हमने हर क्षेत्र में तरक्की की है और उत्पादन भी बहुत बढ़ा है, हालांकि आबादी घटाने के क्षेत्र में उतनी तेजी से काम नहीं हुआ है, जितनी तेजी से संजय जी ने शुरू किया था । संजय जी ने तो अपनी गवर्नमेंट को भी दाव पर लगा दिया था । आज जहां भी जाइए हर जगह भीड़ ही भीड़ दिखाई देती है । बसों में जाइये, रेलों में जाइए । अगर कण्ट्रोल न किया गया तो हम कोई समस्या हल नहीं